



बिहार सरकार
उद्योग विभाग

+91 0612 2547371

+91 85442 99526

<https://biharfoundation.bihar.govt.in>

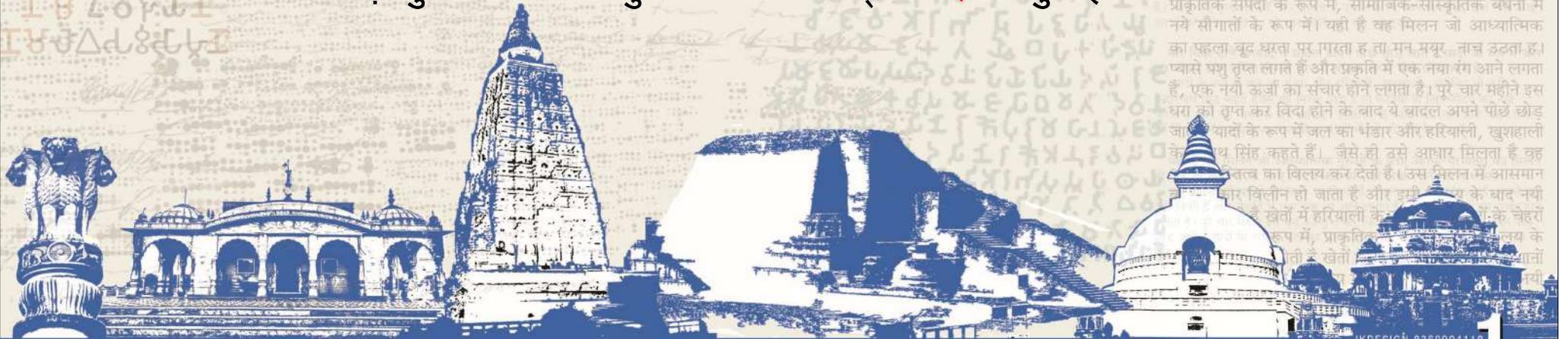


BIHAR
FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

सम्प्रति बिहार

बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति

बिहार के महत्वपूर्ण अखबारों में छपे **सकारात्मक** समाचारों का संकलन
आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी शुक्रवार विक्रम संवत् 2079 | 08 जुलाई 2022



6TH FLOOR, INDIRA BHAWAN, RCS PATH, PATNA-800001. BIHAR, INDIA.

JKDESIGN 8369994118

1

केंद्रीय योजनाओं को सक्रियता से पूरा करेगा बिहार

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि औद्योगिकीकरण को सुनिश्चित करने वाली केंद्र की सभी योजनाओं को बिहार सरकार अत्यंत सक्रियता से पूरा करेगी। वे गुरुवार को दिल्ली के अशोका होटल में हुए इंस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहली एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने बताया कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के तहत बिहार के गया में 1670 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। 1200 एकड़ भूमि अधिगृहीत कर ली गई है और शेष का अधिग्रहण सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए



उद्योग विभाग की तरफ से 50 करोड़ और 33 करोड़ यानी दो किस्तों में कुल 83 करोड़ की रकम आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को उपलब्ध करा दिया गया है। गया के डोभी में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना उद्योग विभाग, बिहार सरकार और बियाडा के द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के

बैठक में 18 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की मौजूदगी में हुई बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कुल 18 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, तेलंगाना के उद्योग मंत्री केटी रामा राव शामिल हुए।

माध्यम से किया जा रहा है। शाहनवाज ने बिहार को 'पीएम मित्र पार्क' दिये जाने की मांग दोहरायी। कहा- पश्चिम चंपारण में 1719 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है। बिहार के पास टेक्सटाइल उद्योगों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित श्रम शक्ति है। कुशीनगर एयरपोर्ट के बनने से बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी के साथ-साथ इंटरनेशनल हवाई कनेक्टिविटी भी बन गई है। ऐसे में बिहार देश का टेक्सटाइल हब

बन सकता है। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बिहार को मित्र पार्क मिलने लिए वकालत की। कहा कि बिहार में अगर टेक्सटाइल उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं तो इस पर जरूर अच्छे से विचार होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने पीएम गति शक्ति पार्ट 2 के लिए 503 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।



सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 08.07.2022 | पृष्ठ सं० 08





मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना **सुविधा: जिलों को भेजी गई** **501 आधुनिक एम्बुलेंस**

पटना, हिन्दुस्तान, 07 जुलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 501 आधुनिक नई एम्बुलेंस को जिलों के लिए रवाना किया। इनमें 275 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 226 बैसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन एम्बुलेंस के परिचालन से आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन सेवा में गुणात्मक सुधार होगा तथा आम लोगों को इसका कामोत्पन्न प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने गुरचार को एक अग्रे मार्ग से 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत इन एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत अच्छा काम हुआ है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मरीजों को समय सीमा के अंदर आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन सेवा उपलब्ध होने से कामोत्पन्न सहूलियत होगी। इस पहल से मरीजों की उच्चतर इलाज की सुविधा वाले अस्पतालों में ले जाने में काफी सुविधा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की पंचवती माताओं, बीमार विधवाओं, गंधीर रूप से बीमार मरीजों एवं बुढ़ाना अस्व मरीजों को इससे तत्काल स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस को रवाना करने के पहले इसके अंदर की व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि आज बेहतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन नई एम्बुलेंस का लोकार्पण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल

275
एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हुई रवाना

226
बैसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल

■ मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य परिवहन सेवा में गुणात्मक सुधार होगा



पटना स्थित एक अग्रे मार्ग से गुरचार को जिलों के लिए आधुनिक एम्बुलेंस रवाना करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय व अन्य।

एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सुविधा के साथ वेंटिलेटर भी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष हमने पुरानी सभी सरकारी 652 एम्बुलेंस को बदलकर उनके स्थान पर एक हजार नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय लिया था। इनमें से 534 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रत्येक प्रखंड के लिए हैं। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सुविधा के साथ-साथ वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर-सह-कार्डियक मॉनिटर, सेटल वैन कैबिनेट्स आदि की सुविधा है। इस प्रकार एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस चलत महान चिकित्सा कक्षा की तरह कार्य करती है। शेष 466 बैसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ऑक्सीजन सुविधा युक्त हैं। इनका उपयोग सामान्य रोगियों के परिवहन में किया जाता है।

एक हजार एम्बुलेंस की खरीद गई है। इनमें से 501 एम्बुलेंस को सभी जिलों के लिए रवाना किया गया है।
मौके उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय,

बिहार पहला राज्य, जहां हर प्रखंड में लोगों को यह सुविधा मिलेगी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज 501 एम्बुलेंस को राज्य के सभी 38 जिलों के लिए रवाना किया गया है। शेष नयी एम्बुलेंस की आपूर्ति प्राप्त होते ही उन्हें भी जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार पहला राज्य होगा, जिसने प्रत्येक प्रखंड में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

अनुपम कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, स्वास्थ्य सचिव के संकेतल कुमार, कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति संजय कुमार सिंह आदि मौजूद थे।

▶ देखें P02





तमिलनाडु के सलेम स्थित पेरियार विश्वविद्यालय की तरह बनेगा पार्क, अमृत महोत्सव के तहत थावे वन परिसर का हुआ है चयन थावे में बनेगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क

विशेष

■ मनीष कुमार भारती

गोपालगंज। बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले के थावे के वन परिसर में बनेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के 75 नगर वन परिसर क्षेत्र को जीव विविधता के संरक्षण व संवर्द्धन के लिहाज से नगर वन योजना से विकसित किया जा रहा है। इसमें शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थावे मंदिर के समीप 12.63 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले वन परिसर क्षेत्र का भी चयन किया गया है। यहाँ तमिलनाडु के सलेम के पेरियार विश्वविद्यालय की तरह ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना है। वन विभाग के अनुसार ऑक्सीजन पार्क को बांस के पौधे लगा कर बनाया जाएगा। बांस दुसरे पौधे की तुलना में 35 फीसदी अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। थावे के प्रस्तावित वन परिसर में तमिलनाडु

75 वन परिसर क्षेत्र को देशभर में जीव विविधता के महत्व के अनुसार किया जा रहा विकसित

07 किमी गोपालगंज शहर से दूर नगर वन परिसर क्षेत्र में पार्क बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

■ ऑक्सीजन पार्क के लिए लगाए जाएंगे भीमा प्रजाति के बांस



थावे में इसी स्थान पर सूबे का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाने की है योजना।

की तरह भीमा प्रजाति के बांस के पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रजाति के पौधे सी से अधिक वर्षों तक खेत में उगे रहते हैं। इन्हें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका विकास भी तेज होता

है। विभाग के अनुसार जल्द ही वन परिसर क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्क बनाने के लिए मुफ़ीद जगह के चयन के साथ पूरी योजना का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने

के लिए पार्क में ओपेन जॉम, बच्चों के लिए झूले व फव्वारे आदि भी लगेंगे। तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क में वॉकिंग पाथ व बैठने के लिए कंक्रीट बेंच भी

बनाने की योजना है, ताकि यहाँ राज्य व देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों से थावे मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालु पहुंच सकें। एक अध्ययन में ऑक्सीजन पार्क तमिलनाडु के पेरियार

वन परिसर में आयोजित कार्यक्रम से पीएम जुड़ेंगे

शुक्रवार को वन महोत्सव पर देशभर के नगर वन परिसर में 75 पौधे लगाए जाएंगे। थावे के प्रस्तावित नगर वन परिसर में पौधरोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ़रेसिंग के जरिए जुड़ेंगे। वे कार्यक्रम में शामिल होने वाले वच्चों के साथ सवाद भी करेंगे।

पार्क के चार फायदे

1. जीव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन में मिलेगी मदद
2. सैर करने वालों की भरपूर ऑक्सीजन से सुधरती सैहत
3. थावे मंदिर में पूजा के लिए आने वाले पर्यटक होंगे आकर्षित
4. पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां

66 थावे में ऑक्सीजन पार्क तमिलनाडु के पेरियार विश्वविद्यालय की तरह बनाने की योजना है। बांस के पौधे से नगर वन परिसर इलाके में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। यह राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क होगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

—रामसुंदर एम, कम प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज

विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ है। छात्र वहां पढ़ाई करते हुए सुकून महसूस करते हैं। भरपूर ऑक्सीजन मिलने से पढ़ाई पर भी उनका फोकस बढ़ा पाया गया है।



पर्यटन व पुरातात्विक स्थल निशुल्क देख सकेंगे बच्चे

बिहार दर्शन

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत राज्य के स्कूली बच्चे अब ज्यादातर पर्यटन व पुरातत्व स्थलों का परिभ्रमण निशुल्क कर पायेंगे। भीड़ वाली जगहों मसलन राजगीर का रोपवे, जूव नेचर सफारी का भ्रमण पूर्व के नियमों के तहत ही होगा।

बिहार एवं पटना संग्रहालय में बच्चों के लिए निर्धारित प्रवेश शुल्क क्रमशः 20 एवं 5 रुपए यथावत ही रहेगा। हाल ही में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार दर्शन योजना को लेकर कई बड़े फैसले किये गये। बैठक में शिक्षा, पर्यटन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, कला संस्कृति एवं वित्त विभाग के आलाधिकारी मौजूद रहे। राज्य के सभी पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थलों में बिहार दर्शन के तहत छात्र-छात्राओं को प्रवेश शुल्क से मुक्त रखने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने रखा।

जिन स्कूलों में भूमि, वहां होगी नर्सरी विकसित

बैठक में तय हुआ कि राज्य के जिन विद्यालयों में पर्याप्त भूमि है वहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नर्सरी विकसित की जाएगी। इस कार्य में वन विभाग के कर्मी शिक्षा विभाग का सहयोग करेंगे।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए बच्चों को वन क्षेत्र एवं नर्सरी के परिभ्रमण की भी आवश्यकता जताई। कला संस्कृति सचिव वंदना प्रयेसी को जिम्मा दिया गया कि राज्य के 28 क्षेत्रीय संग्रहालयों में बच्चों के परिभ्रमण योग्य सुविधाएं विकसित कराएं। बैठक में यह बात प्रमुखता से उठी कि शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रति विद्यालय बिहार दर्शन योजना में 20,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि बच्चों के आवागमन में ही खर्च हो जाती है। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निशुल्क प्रवेश वाले स्थलों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।



नलकूपों में मोबाइल पंप कंट्रोलर लगाने के लिए बिहार पुरस्कृत

सम्मान

- लघु जल संसाधन विभाग को केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने किया पुरस्कृत

संवाददाता पटना

राज्य में राजकीय नलकूपों में मोबाइल पंप कंट्रोलर लगाने के लिए लघु जल संसाधन विभाग को केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने नयी दिल्ली में पुरस्कृत किया है. विभाग की तरफ से यह पुरस्कार विशेष सचिव सह परियोजना संयोजक, नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट गोपाल मीणा



ने ग्रहण किया. वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रियान्वित यह महत्वपूर्ण योजना मुख्यतः इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिद्धांत पर आधारित है. लघु जल संसाधन विभाग ने करीब चार करोड़ 38 हजार रुपये की लागत से राज्य के 3156 राजकीय नलकूपों पर मोबाइल पंप

कंट्रोलर लगाया है. यह लागत औसतन कम है. इस कंट्रोलर के लगने से नलकूपों का संचालन किसी भी स्थान से मोबाइल फोन या इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकेगा. साथ ही नलकूपों के संचालन से संबंधित पटवन ब्योरा, बिजली खपत, नलकूपों

के चलने की अवधि, जलस्राव आदि के आंकड़े भी प्राप्त किये जा सकेंगे. वहीं, राजकीय नलकूपों पर मोबाइल पंप कंट्रोलर लगने से लो-वोल्टेज, सिंगल फेज करंट आदि के कारण मोटर पंप के खराब होने की समस्या भी बहुत कम हो जायेगी. इस बैठक में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज कुमार और विश्व बैंक की टीम लीडर अंजु गौर ने लघु जल संसाधन विभाग के इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना की. साथ ही उन्होंने योजना के तहत बेहतर लाभ की व्यवस्था विकसित करने के लिए मदद का आश्वासन दिया. यह जानकारी तकनीकी पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने दी.



सौजन्य से प्रभात खबर | पटना | 08.07.2022 | पृष्ठ सं० 10



बिहार कोविड अपडेट

⇒ कुल सक्रिय मामलों की संख्या	1573
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान नए पॉज़िटिव मामलों की संख्या	343
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या	158
⇒ कुल वैक्सीनेशन	13,80,38,885
⇒ कम से कम एक डोज	7,15,21,619
⇒ पूर्ण वैक्सीनेटेड	6,24,12,773





बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

विदेश अवस्थित चैप्टर



कतर



दक्षिण कोरिया



जापान



हॉंग कॉंग



यू.ए.ई.



सिंगापुर



बहरीन



न्यूजीलैंड



कनाडा



यू.एस.ए.



ऑस्ट्रेलिया



सऊदी अरब

देश अवस्थित चैप्टर



मुम्बई

हैदराबाद

पुणे

चेन्नई

नागपुर

गुजरात

कोलकाता

वाराणसी

गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन के जुड़ने के लिए

बिहार फाउन्डेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। वर्तमान में बिहार फाउन्डेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं। बिहार फाउन्डेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें -

<https://biharfoundation.bihar.gov.in>